नुकसानदायक है खेत और मिल का विवाद

लेखक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं,अब स्वतंत्र टिप्पणीकार। देश के तीन राज्यों में गन्ना और चीनी को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रित उनका यह आलेख

धर्मेंद्र पाल सिंह

आखिर उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलें चालू करवाने में कामयाब हो गई। निजी मिल मालिकों से कड़ी सौदेबाजी के बाद समाजवादी सरकार गन्ना किसानों को पिछले साल का रेट दिलवाने में तो सफल हो गई लेकिन उसे कर के रूप में चीनी मिलो को 880 करोड़ रुपए की छूट देनी पड़ी है। लखीमपुर खीरी में एक गन्ना किसान द्वारा आत्महत्या किये जाने के बाद पूरे राज्य में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। उत्तर प्रदेश के किसान इस कारण भी बेचैन हैं क्योंकि गेंहूं की बुआई का मौसम शुरू हो चुका है जबकि गन्ने की कटाई शुरू भी नहीं हुई। चीनी मिल बंद होने से छोटे किसानों ने ने-पौने दाम पर गन्ना बेचना शुरू कर दिया था। बाद में आंदोलन के तेवर कड़े हो जाने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने लगी थी।

दरअसल गन्ना किसानों की समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के गन्ना उत्पादक अन्य प्रमुख राज्यों में भी आग लगी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थिति विस्फोटक है। कर्नाटक विधानसभा के सामने एक गन्ना किसान खुदकुशी कर चुका है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी एक किसान ने पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। महाराष्ट्र में दो किसानों द्वारा आत्महत्या का समाचार है। हर साल जाड़ा आते ही गन्ना किसानों और मिल मालिकों का विवाद शुरू हो जाता है। इतने बरस बीत जाने के बाद भी सरकार गन्ने की कीमत तय करने का एक सर्वमान्य फार्मूला तय नहीं कर पाई है। हर राज्य और राज्य के अलग-अलग इलाकों में किसानो को गन्ने की अलग-अलग कीमत मिलती है। महाराष्ट्र में तो अधिकांश चीनी मिलों पर एनसीपी, कांग्रेस और भाजपा नेताओं का कब्जा है जो किसानों का हितैषी होने का दावा करते हैं, फिर भी वहां किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं सर्वाधिक हैं।

मिल मालिकों के संगठन इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के अनुसार पिछले साल अक्टूबर-नवम्बर में देश में 400 चीनी फैक्ट्रियां चालू थीं जबकि इस वर्ष इन दो महीनों में मात्र 208 चलीं। गत वर्ष नवम्बर में 22.4 लाख टन चीनी बनी जबकि इस साल उत्पादन घटकर एक तिहाई (आठ लाख टन) रह गया। उत्तर प्रदेश में पिछले साल इस अवधि में 99 मिल चल रही थीं जबकि इस वर्ष केवल 22 चली। इसी प्रकार महाराष्ट्र में गत वर्ष 149 मिल चालू थीं, इस वर्ष मात्र 102 चलीं। यह स्थिति देखकर तो लगता है कि इस साल चीनी का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। नतीजन देश में चीनी की कीमतों में उछाल आना तय है। गन्ने की कीमत तर्क संगत बनाने के लिए सरकार ने सी.रंगराजन कमेटी गठित की थी। कमेटी ने खुले बाजार में बिक्री के लिए चीनी जारी करने की व्यवस्था समाप्त करने का सुझाव दिया जिसे केंद्र सरकार ने गत अप्रैल में मंजूर कर लिया, लेकिन गन्ने की कीमत तय करने पर अभी तक विवाद बना हुआ है। राज्य सरकारें और किसान रंगराजन कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ हैं जबकि मिल मालिक उसे लागू करना चाहते हैं। मिल मालिकों का तर्क है कि पिछले साल के मुकाबले चीनी का बाजार भाव कम हो गया है इसलिए उनके लिए 225 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा कीमत चुकाना कठिन है। दूसरी ओर किसानों का तर्क है कि महंगाई के कारण एक साल में गन्ने के लागत मूल्य में 23 फीसदी इजाफा हो चुका है इसलिए उन्हें बढ़ी कीमत दी जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में पिछले साल चीनी मीलों ने न्यूनतम 280 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गन्ना खरीदा था लेकिन इस बार मिल मालिक 55 रुपए प्रति क्विंटल दाम घटाना चाहते थे। उनका दावा है कि पिछले साल ऊंचे दाम पर गन्ना खरीदने के कारण उन्हें तीन हजार करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। समझौते के बाद वे पुरानी कीमत देने को तो राजी हो गए, पर किसानों को भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के किसान महंगाई के कारण बढ़ी लागत को देखकर 300-350 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहे थे जो अब उन्होंने घटाकर 265 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। इसके बावजूद मिल मालिक झुकने को तैयार नहीं हैं। समस्या की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तीन मंत्रियों की एक समिति गठित की है, लेकिन इस बार भी समस्या के स्थायी हल की उम्मीद नहीं की जा सकता। जो भी फैसला होगा वह चुनावी गणित को नाप-तोलकर लिया जाएगा। बतौर समझौता केंद्र सरकार चीनी मिलो को बैंकों से ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया कराने का पत्ता फेंक रही है। सन् 2007 में भी सरकार ने चीनी मिलो को सस्ता कर्ज दिलाकर समझौता कराया था।

मिल मालिकों का दावा है कि पिछले तीन साल में गन्ने की कीमत 70 प्रतिशत बढ़ गई है जबकि चीनी का मूल्य केवल आठ फीसदी बढ़ा है। अक्टूबर 2012 में चीनी का भाव 37 रुपए प्रति किलो था जो अब घटकर 30-31 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। मौजूदा गन्ना मूल्य पर एक किलो चीनी बनाने की लागत 30 से 31 रुपए के बीच आती है। मालिकों का सवाल है कि ऐसे में मिल चलाना कैसे संभव है ? आज अधिकांश चीनी मिलों की साख गहरे संकट में है जिस कारण राष्ट्रीयकृत बैंक उन्हें ऋण देने से झिझक रहे हैं। सरकार इन्हें कर्ज दिलाकर सरकार चीनी मिलो को मौजूदा संकट से निकाल सकती है लेकिन किसानों के बकाया 24 अरब रुपए का क्या होगा ? देश में करीब 40 लाख हेक्टयेर जमीन पर गन्ना बोया जाता है और इस नकद फसल की पैदावार पर पांच करोड़ किसान निर्भर हैं। गन्ना उद्योग से 20 लाख श्रमिकों को भी रोजगार मिलता है। मोटे तौर पर प्रति हेक्टयेर 70 टन गन्ना पैदा होता है। पिछले साल देश में 2.51 करोड़ टन चीनी बनी जो घरेलू खपत (2.3 करोड़ टन) को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। भारत में दो-तिहाई गन्ने से चीनी और शेष एक तिहाई से गुड़ और खांडसारी बनती है जिसकी खपत ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होती है। ब्राजील और भारत दुनिया के अग्रणी गन्ना उत्पादक देश हैं लेकिन हमारे यहां चीनी की खपत ब्राजील से दो गुना होती है। आज देश में चीनी उद्योग लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का है और इस पर आए संकट को नजरअंदाज करना देश की आर्थिक सेहत के लिए सही नहीं होगा।